

प्रेस विज्ञप्ति

23 मार्च 2013

चुनाव व राजनीतिक सुधारों पर 9 वां वार्षिक सम्मेलन

हमारे प्रजातंत्र का सबसे बड़ा खतरा कारपोरेट दुनिया का प्रवेश व अघोषित पैसों को उपयोग है। ये दोनो चीजें राजीनिक दलों में अन्दर तक प्रवेश कर गई है।

कुमार केतकर ने कहा कि आज राजनीति में पैसो का प्रवेश और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की कमी ने 'कारपोरेट फासीवाद' को जन्म दिया है। यह नया परिवर्तन राजनैतिक दलों के अन्दर आया है वह भारतीय प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 9 वां वार्षिक सम्मेलन एडीआर व राष्ट्रीय इलेक्शन वांच द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसके उद्घाटन सत्र में कुमार केतकर ने इस बात पर जोर दिया कि हम देश के नागरिकों को राजनीति विरोधी नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सुदृढ़ प्रजातंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। अरुणा रॉय, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ने इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राजनैतिक दलों में वित्तीय पारदर्शिता का आना सबसे जरूरी माना। प्रो. त्रिलोचन शास्त्री ने कहा कि हम राजनीति व शासन में जो बीमारी देख रहे हैं वह वास्तव में एक 'सुनामी' है। इस सुनामी का स्रोत चुनाव में धन का प्रयोग व दलों द्वारा चुनाव वितरण की राजनीति से जुड़ा है।

विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया ताकि वे राजनैतिक दलों को कानून के दायरे में लाने के मुद्दे पर अपनी राय दे सकें। इस कानून पर विचार देते हुए सीपीआई की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर ने कहा कि राजनैतिक दल आरटीआई के दायरे में आना चाहिए और राजनैतिक दलों में आंतरिक प्रजातंत्र होना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि राजनैतिक दलों को कारपोरेट जगत से मिलने वाले पैसे पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। यह भी कहा कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ कोई शिकायत हो तो उनका निबटारा फास्ट ट्रेक कोर्ट से होना चाहिए। अन्य कई राजनीतिक पार्टियों से आए वक्ताओं ने चुनाव में 'स्टेट फण्डिंग' का सुझाव दिया। दलों के अन्दर महिलाओं को टिकिट देने का आरक्षण होना चाहिए। राजस्थान कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेट्री ने सूचना दी कि अम्बिका सोनी के नेतृत्व में कांग्रेस दल ने एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी चुनाव व राजनैतिक सुधारों पर अपनी राय देगी।

विभिन्न राज्यों के राज्य इलेक्शन वांच के प्रतिनिधियों व नेशनल इलेक्शन वांच के समन्वयकों ने चुनाव सुधार कार्यक्रमों को सबके सामने प्रस्तुत किया। वोटिंग मशीन में नियम 49-0 के तहत एक बटन अवश्य होना चाहिए। यह मांग सभी लोगों ने उठाई। एम.एल.ए. व एम.पी. के क्रियाकलापों का विश्लेषण होना चाहिए। एम.एल.ए. व एम पी द्वारा खर्च किए गए फण्ड की समन्वित रिपोर्ट बननी चाहिए और यह रिपोर्ट हर वर्ष संसद व विधानसभा में प्रस्तुत होनी चाहिए

और उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। एक और बात जिस पर चर्चा हुई कि राज्य चुनाव आयोग पंचायत व स्थानीय संस्थाओं में होने वाले चुनावों प्रत्याशियों के एफिडेविट नहीं दे पा रहे हैं। इस में उड़ीसा व पंजाब की घटनाओं की चर्चा हुई। यह भी चर्चा हुई कि चुनाव प्रक्रिया के बारे में युवा पीढ़ी को संवेदनशील किए जाने की आवश्यकता है।

जन आन्दोलन और चुनाव के रिश्तों पर विचार रखते हुए अरुणा रॉय ने कहा कि राजनीति में जन आन्दोलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह चुनावी राजनीति नहीं है परन्तु यह महत्वपूर्ण है। पीयूसीएल के अध्यक्ष प्रेमकृष्ण शर्मा ने कहा जन आन्दोलनों का पहला सिद्धान्त यह होना चाहिए कि वे अपनी राजनैतिक सोच व लोगों के विचारों को सामने रखे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नागरिक आन्दोलनों के माध्यमों से अपनी बात अभिव्यक्त न कर सके तो जब राजनेता सत्ता में आएंगे तो वे आन्दोलनों को रोक देंगे। एमकेएसएस के भंवर मेघवंशी ने कहा कि इलेक्ट्रोल व नॉन इलेक्ट्रोल राजनीति में बड़ा द्वन्द है। जन आन्दोलनों निडर होकर लोगों की भावना को सबके सामने ला सकते हैं।

नारायण बारेठ ने राजनैतिक दलों के टिकिट वितरण की बात को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रखते हुए कहा कि पहले लोगों को टिकिट सामाजिक व राष्ट्रीय आन्दोलनों से जुड़े मुद्दों के आधार पर मिलते थे इनमें से नेता बनते थे अब वे किसी 'socialite movements' मिलते हैं। अब गैस ऐजेन्सी, पेट्रोल पम्प, टाल कांट्रेक्ट, खान व शोपिंग माल होने पर टिकिट मिलते हैं।

<p>Ms. Aruna Roy</p> <p>Rajasthan Election Watch,</p> <p>E: arunaroy@gmail.com</p>	<p>Ms. Renuka Pamecha</p> <p>Rajasthan Election Watch,</p> <p>M: +91 9314503785</p> <p>E: renukapamecha@yahoo.co.in</p>	<p>Mr. Nikhil Dey</p> <p>Rajasthan Election Watch,</p> <p>E: nikhildey@gmail.com</p>	<p>Journalist Helpline:</p> <p>+91-8010394248</p> <p>adr@adrindia.org</p>
---	---	--	--

<p>Mr. Anil Bairwal</p> <p>National Coordinator</p> <p>National Election Watch, and</p> <p>Association for Democratic Reforms</p> <p>011 4081 7601,</p> <p>+91 9999310100</p> <p>adr@adrIndia.org,</p> <p>anil@adrIndia.org</p>	<p>Prof Trilochan Sastry</p> <p>IIM Bangalore</p> <p>Founder Member,</p> <p>National Election Watch,</p> <p>Association for Democratic Reforms</p> <p>+919448353285,</p> <p>trilochans@iimb.ernet.in</p>	<p>Prof Jagdeep Chhokar</p> <p>IIM Ahmedabad (Retd.)</p> <p>Founder Member</p> <p>National Election Watch,</p> <p>Association for Democratic Reforms</p> <p>+919999620944</p> <p>jchhokar@gmail.com</p>
---	---	--

RSVP:

<p>Ms. Mashqura Fareedi (ADR and NEW)</p> <p>M: +91 9953595359</p> <p>E: adr@adrindia.org, mashqura@adrindia.org</p>	<p>Mr. Kamal Tank (Rajasthan Election Watch)</p> <p>M: +91-94134-57292</p> <p>E: kamalrti@gmail.com</p>
--	--